EDITORIAL

SEPTEMBER 2, 2016 NATIONWIDE STRIKE

The central trade unions federations of various industries like Banks, LIC, Postal, Defense, PSUs State Govt. employees, Co-opertaives all have given a clarion call to the lakhs of workers and employees to observe One Day Strike on Sept. 2 to fight out the onslaught.

The present Govt intensified its attacks like dismantling the hard won labour laws, disinvestment and strategic sale of even profit making PSUs, Hundred percent FDI even in vital sectors like Defense equipment manufacturing, Pharma industries, Real estate, Ratail store Etc. The entire working class feels that these attack of the Govt will have its serious impact on the future of workers and even to the safety and security of our beloved country, India.

The labour laws like 1926, trade union Act 1947, industrial dispute act 1948, industrial establishment act are being dismantled with, 1936 payment of wages Act, and 1948 minimum wages act in the name of labour code 2015. They want to give up their responsibility of even fixing minimum wage to the very down trodden sections like contract labourers. The agreed minimum wage of Rs. 10,000 even not is implemented.

In the name of Small factories Act, startup companies, they assure “No labour law zones, “The safety and security of workers and employees are put into danger by compelling nights shifts. Even the poor inspecting method of factories will not be there in future in the name of abolition of “Inspection Raj”. Each budget session, lakhs of crores concession is given to Corporate and more attacks on indirect taxes to have common people to suffer. Health, education, SC/ST welfare are facing cuts in budget, Govt is not able to control the Prices of essential things, public distribution system is systematically being dismantled.

The public utility departments like Railways, Our Telecom, Port, Electricity, FCI all are facing the heat of liberalization. They want to create separate Railway track corporation. The railway coach factories are hand over to foreign multinationals. FCI is also facing the problem of bifurcation. For Defense session, USA Companies are allured freely and this leads a dangerous situation.

Farmers and agri-labourers are suffering like any thing, not only because of natural havocs but because of polices of govt. The death of lakhs of farmers are only on account of debt trap.

Taking all theses negative developments the entire Trade unions of this country decided to launch One day Strike on Sept. 2/2016. In telecom also dismantling is going in the form of Tower corporation, OFC outsourcing, etc. Disinvestment is knocking our doors. Deloitte is threat to our jobs. So it is our duty to be part of main stream struggle.

Let us do our duty by Participating enmasse. Hold the banner of working class unity high. Participate in 2nd September strike.

संपादकीय

दो सितम्बर 2016 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल

सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों एवं औद्योगिक महासंघों जैसे बीमा, बैंक, डाक, डिफेन्स, कोयला, बिजली, लोक उपक्रम, राज्य सरकारों के श्रम संगठन, सहकारी होम के संगठनों ने लाखों मजदूरों एवं कर्मचारियों को 2 सितम्बर 2016 को एक दिवसीय पूर्ण हड़ताल करने का आह्वान किया है।

वर्तमान सरकार ने कठोर संघर्ष से प्राप्त श्रम कानूनों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है, विनिवेश एवं लाभ अर्जित करने वाले लोक उपक्रमों का विक्रय के पथ पर है। शत–प्रतिशत विदेशी विनिवेश यहां तक कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र, दवा उद्योग, रियल स्टेट, खुदरा विक्रय में भी विनिवेश की खुली छूट देने की घोषणा हो रही है। समस्त मेहनतकश आवाम इस मुतल्लिक चिंतित हैं कि प्रकाशान्तर में इन जनविरोधी नीतियों का शिकार श्रमिक वर्ग होगा यहां तक यह हमारे प्यारे भारत देश के लिए भी घातक हो सकता है।

श्रम कानून 1926, श्रमिक संगठन एटक 1947, औद्योगिक विवाद एक्ट 1948 औद्योगिक स्थापना एक्ट आदि सहित मजदूरी भुगतान एक्ट 1936, एवं न्यूनतम वेतन एक्ट 1948 को लेबर कोड 2015 के नाम पर दफनाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार निम्नस्तरीय ठेका श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी तय करने के अपने दायित्व से किनारा कर रही है। मान्य न्यूनतम वेतन दस हजार रूपये लागू नहीं हो पाया है।

छोटे कारखाने एवं कम्पनी स्थापना को श्रमिक कानून रहित क्षेत्र का नाम दिया जा रहा है। मजदूरों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा समाप्त की जा रही है। यहां तक कि कारखानों के निरीक्षण पद्धति को "इन्सपेक्सन राज" की समाप्ति के नाम पर समाप्त किया जा रहा है। हर बजट सत्र में निजी क्षेत्रों में लाखों करोड़ रूपये की छूट दी जा रही है और अपरोदा करों के माध्यम से आम एवं निरीह आम जन पर प्रहार जारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, दलित कल्याण के लिए कोष आह्वान में कटौती जारी है। सरकार आवश्यक सामग्रियों के मूल्य नियंत्रण में पूर्णतया विफल रही है। जन वितरण प्रणाली को बकायदा समाप्त किया जा रहा है।

जन उपयोग सरकारी विभागों जैसे रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, बिजली, खाद्य निगम आदि उदारीकरण का ताप झेल रहे हैं। ये रेलवे में अलग ट्रैक निगम बनाना चाहते हैं। रेलवे के कारखाने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हस्तगत कराये जा रहे हैं। बीएसएनएल से अलग टावर कंपनी की घोषणा की जा चुकी है। खाद्य निगम का त्रिभाग करने की मंसूबा जग जाहिर है। सुरक्षा उत्पादन को संयुक्त राज्य अमेरिका को खुले रूप से प्रवेश देने की प्रक्रिया है, जो देश के लिए घातक साबित हो सकता है।

खेतिहर किसान एवं खेत मजदूर केवल प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं अपितु सरकारी नीतियों के कारण तबाह हैं। कर्ज में लदे किसानों की आत्महत्या आम बात बन चुकी है। उपयुक्त सभी विनाशकारी स्थितियों के आलोक में समस्त राष्ट्रीय पैमाने पर श्रमिक संगठनों ने अगामी 2 सितम्बर 2016 को एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर जाने का निश्चिय किया है।

हमारे भारत संचार निगम को भी टावर कम्पनी के द्वारा तथा ओ.एफ.सी. का आउटसोर्सिंग करके तबाह करने की साजिश जारी है।

डियोलाइट के अनुशंसा ने नौकरी का खतरा पैदा कर दिया है। नियम 55 (II) (बी) का भय दिखाया जा रहा है। अतः हम बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों को भी मुख्यधारा में शामिल होना लाजिमी है।

इस परिपेक्ष में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2016 को दिल्ली में एन.एफ.टी.ई. के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से 2 सितम्बर के हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है।

आइये हम देश के मेहनतकश आवाम के पुनीत कार्रवाई में शामिल होकर मजदूर वर्ग के एकता के आवाज को बुलंद करें तथा श्रमिकों के झंडे को उच्च शिखर पर लहरायें। सभी साथी 2 सितम्बर 2016 में हड़ताल में शामिल हों।